बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 29

खतरनाक बढ़ोतरी

जानकारी के मुताबिक सरकार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण में काम आने वाले अहम घटकों के शुल्क में और अधिक इजाफा करने पर विचार कर रही है। खासतौर पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के बारे में जानकारी है कि वह कंप्रेसर पर लगने वाले आयात शुल्क में इजाफा करने पर विचार कर रहा है। ये कंप्रेसर एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे प्रशीतक उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा इनका इस्तेमाल प्री-कोटेड स्टील शीट और कॉपर ट्यूब में भी किया जाता है। ये चीजें भी उपरोक्त वस्तुओं की निर्माण प्रक्रिया में काम आती हैं। गत वर्ष भी कंप्रेसर पर लगने वाले शुल्क को 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी किया गया था। हालांकि इसके पीछे मूल विचार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि महंगे आयात का खमियाजा घरेलू उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा। केवल आयात शुल्क बढ़ाने से उपभोक्ताओं या उत्पादकों के लिए हालात में शायद ही कोई खास बदलाव आए। करों को लेकर अतीत में जो भी बदलाव हुए उनका असर उपभोक्ताओं पर ही पड़ा। पहले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और उसके बाद तमाम वातानुकूलकों, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटरों पर शुल्क वृद्धि। पिछली बढ़ोतरी में शुल्क दर दोगुनी बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गई।

कहा जा रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय चालू खाते के बढ़ते घाटे को लेकर चिंतित है। जुलाई-सितंबर 2018 तिमाही में यह घाटा जीडीपी के 3 फीसदी के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था। शुल्क में बढ़ोतरी से आयातित वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा और चालू खाते के घाटे में कमी आएगी। हालांकि यह तरीका दूरदर्शी नहीं प्रतीत होता। इसके दीर्घकालिक परिणाम बहुत जोखिम भरे हो सकते हैं। इससे बड़ी कंपनियां अपना विनिर्माण विदेशों में स्थानांतरित करने पर भी विचार कर सकती हैं। एलसीडीपी टेलीविजन के पैनल पर शुल्क बढ़ाने का नतीजा उसका विनिर्माण वियतनाम स्थानांतरित किए जाने के रूप में सामने आ चुका है।

चालू खाते के घाटे की मौजूदा समस्या से निपटने का एकमात्र तरीका यह है कि निर्यात में स्थायित्व के साथ इजाफा किया जाए। यह लक्ष्य कैसे हासिल होगा? इसके लिए अनिवार्य तौर पर देश में एक ऐसा प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र विकसित करना होगा जो वैश्विक स्तर पर एकीकृत हो। परंतु उसके लिए जरूरी यह है कि सरकार इस प्रकार एकबारगी शुल्क में इजाफा नहीं करे। विनिर्माताओं को भी उनकी लागत को लेकर सुरक्षा का बोध होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे अपना कामकाज विदेशों में स्थापित करेंगे जहां घटकों की उपलब्धता और लागत के बारे में कुछ सुनिश्चितता होगी। शुल्क में बढ़ोतरी से देश के विनिर्माण उपक्रम हतोत्साहित होते हैं क्योंकि इसका असर वैश्विक आपूर्ति शृंखला में उनकी स्थिति पर पड़ता है। यह आपूर्ति शृंखला विनिर्माण क्षेत्र के लिए अहम है। यह बात इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण क्षेत्र पर खासतौर पर लागू होती है। अगर निर्यात में इजाफा करने और अर्थव्यवस्था में आयात की गहनता कम करने के समन्वित प्रयास किए जाएं तो हालात में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। बहुत खेद की बात है कि उद्योग जगत भी इस मसले पर साफ-साफ ढंग से बात नहीं कर रहा है। वह अंतिम उत्पाद पर शुल्क वृद्धि के स्वागत को तत्पर दिखता है क्योंकि इसमें घरेलू बाजार और उत्पादकों के संरक्षण का भाव निहित होता है। परंतु संरक्षणवादी नीति को किसी क्षेत्र के लाभ के लिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह बहुत आवश्यक है कि शुल्क दरों का कम रहना सुनिश्चित किया जाए और कॉर्पोरेट जगत से भी ऐसी मांग लगातार उठ रही है। इस बीच सरकार को भी यह समझना चाहिए कि वह ऐसे रास्ते पर नहीं चल सकती जो दीर्घावधि में विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो।

विनय सिन्हा

रिजर्व बैंक के नए गवर्नर का समझदारी वाला कदम

5 अरब डॉलर का स्वैप केंद्रीय बैंक के नकदी प्रबंधन उपायों का एक स्थायी हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसके इस्तेमाल की आवृत्ति डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल पर निर्भर करेगी। बता रहे हैं तमाल बंद्योपाध्याय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तीन साल के अमेरिकी डॉलर एवं भारतीय रुपये की खरीद/बिक्री से जुड़ा स्वैप ऑक्शन 26 मार्च को आयोजित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बैंक के इस निर्णय से फॉरवर्ड प्रीमियम (ऐसी स्थिति जिसमें किसी मुद्रा की भविष्य में अनुमानित कीमत हाजिर भाव से अधिक होती है) नीचे जा रहा है, जिससे कंपनियों को विदेशी में ली गई उनकी उधारी पर हेजिंग खर्च कम करने में मदद मिल रही है।

हाल में आरबीआई ने वित्तीय प्रणाली में नकदी डालने के लिए कई अनूठे उपाय किए हैं और 'करेंसी स्वैप' इन्हीं में एक है। वैसे आरबीआई पहले भी इस रास्ते नकदी मुहैया करा चुका है, लेकिन ऐसा उन मुश्किल परिस्थितियों में किया गया था जब स्थानीय मुद्रा पर दबाव खासा बढ़ गया था।

करेंसी स्वैप से आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन से जुड़े उपायों में विविधता आती है। परंपरागत तौर पर नकद आरक्षित अनुपात (केंद्रीय बैंक के पास बैंकों द्वारा रखी जाने वाली नकदी, जिस पर बैंकों को कोई ब्याज भी नहीं मिलता है) में कटौती लंबे समय तक नकदी बहाल करने का एक परंपरागत साधन रहा है। इन दिनों केंद्रीय बैंक खुला बाजार परिचालन (ओपन मार्केट ऑपरेशन) के जरिये नकदी प्रवाहित करने को अधिक तरजीह देता रहा है। ओएमओ के जरिये आरबीआई बैंकों से बॉन्ड खरीदता है और इसके एवज में रकम निर्गत करता है।

करेंसी स्वैप नीलामी के तहत आरबीआई बैंकों से डॉलर खरीदेगा और इसके समतुल्य रकम जारी करेगा। इस कवायद के तहत तीन साल के लिए वित्तीय प्रणाली में 35,000 करोड़ रुपये नकदी आएगी, जिसके बाद बैंक आरबीआई से दोबारा डॉलर खरीदेंगे। इस अवधि में रुपये में संभावित गिरावट से निपटने के लिए बैंक नीलामी के समय तय होने वाले स्वैप खर्च का भुगतान करेंगे। स्थानीय मुद्रा में गिरावट अधिक आई तो बैंक की देनदारी निश्चित होगी और आरबीआई पर भी विनिमय जोखिम का दबाव नहीं होगा, क्योंकि इसके पास खासी मात्रा में डॉलर हैं। केंद्रीय बैंक को तीन साल बाद बाजार से डॉलर खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगी।

वर्ष 2013 में जब रुपया डॉलर के मुकाबले तेजी से गिर रहा था उस समय भारत के सामने सबसे विकट चालू खाते का घाटा मुंह बाए खड़ा था। उस समय बैंकिंग प्रणाली ने फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट बैंक अकाउंट (एफसीएनआर-बी) के जरिये 26 अरब डॉलर रकम जुटाई थी, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई। ऐसी रकम जुटाने (और इनके बदले रुपये लेने) के लिए आरबीआई ने भी बैंकों को खासा प्रोत्साहित किया। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने बैंकों को तत्कालीन डॉलर/रुपये की स्वैप रेट पर काफी छूट मुहैया कराई। ये जमा रकम नवंबर 2017 में परिपक्व हुई थी।

नीलामी में अंतिम स्वैप रेट जानने के लिए हमें 26 मार्च तक इंतजार करना होगा। चूंकि, स्थानीय मुद्रा अच्छा प्रदर्शन कर रही है और विदेशी मुद्रा भंडार जमा करने की भी कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए आरबीआई शायद ही इस बार बैंकों को छूट की पेशकश करेगा। 2013 में परिस्थितियां प्रतिकूल थीं और देश को विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत थी, इस वजह से इसने स्वैप लागत में कमी की थी। मौजूदा वित्त वर्ष में आरबीआई ने अब तक ओएमओ से 3 लाख करोड़ रुपये रकम डाली है। आखिर इसने यह नया उपाय क्यों चुना है और इसके क्या फायदे हैं? आरबीआई लागातार बॉन्ड खरीदकर नकदी का प्रवाह बनाए रख रहा है, लेकिन देश में आम चुनाव के कारण वित्तीय प्रणाली में अधिक से अधिक नकदी आएगी और उसी गति से इससे बाहर निकलेगी। इसके अलावा कंपनियां भी मार्च तिमाही के लिए अग्रिम कर का भुगतान कर रही हैं। जनवरी में मुद्रा प्रसार 19.87 लाख करोड़ रुपये था, जो एक साल पहले के 16.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। बैंकिंग प्रणाली में साख-जमा अनुपात (क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो) कई महीनों से करीब 78 प्रतिशत रहा है। यह अधिक है, लेकिन इससे भी अधिक इन्क्रीमेंट क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो है, जो पिछले कुछ समय से 100 प्रतिशत से अधिक रहा है।

प्रत्येक 100 रुपये जमा के लिए बैंकों को सरकारी बॉन्ड में 19.5 रुपये निवेश करना है और 4 रुपये सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखना है। चूंकि, जमा रकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, इसलिए बैंक अपनी पूरी नई जमा रकम और पूंजी उधार देने में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सिलसिला लगातार चला तो आरबीआई द्वारा दरों में कटौती के बाद भी रकम पर आई लागत नीचे नहीं आ सकती है।

इस नए प्रयोग के लिए मौजूदा समय उचित है, क्योंकि हाल में ही चलन में आए वॉलंटरी रिटेंशन रूट (वीआरआर) के जरिये विदेशी मुद्रा प्रवाह शुरू हो गया है। आरबीआई ने अक्टूबर 2018 में भारतीय बॉन्ड बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन इसे मार्च के शुरू में अंतिम रूप दिया गया और अब यह बड़े पैमाने पर नकदी आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) कर्ज से लदी एस्सार स्टील के लिए आर्सेलरमित्तल की 42,000 करोड़ रुपये बोली को हरी झंडी दे चुका है, जिससे 6 अरब डॉलर का प्रवाह और बढ़ेगा। इससे आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 402 अरब डॉलर हो जाएगा। इस नए उपाय से वित्तीय प्रणाली में नकदी तो बढ़ेगी ही, साथ ही विदेश में रकम जुटाने वाली भारतीय कंपनियों के हेजिंग खर्च में भी कमी आएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो नकदी सृजन के अलावा इस नई युक्ति से धन के लिए लालायित भारतीय कंपनियों के लिए पूंजी का वैकल्पिक स्रोत भी खुल जाएगा। खासकर इससे उन कंपनियों को लाभ मिलेगा, जो नई परियोजनाओं में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय बैंकिंग प्रणाली से उन्हें नकदी नहीं मिल रही है। हालांकि इससे सरकारी बॉन्ड पर प्राप्तियां बढ़ सकती हैं। आरबीआई द्वारा लगातार बॉन्ड खरीदारी से लंबी अवधि के बॉन्ड पर प्राप्तियां कम रही हैं। आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में अनिश्चितता पर अंकुश लगाने के लिए जब डॉलर बेचता है तब प्रणाली से नकदी निकल जाती है (प्रत्येक डॉलर की बिक्री से इतनी ही समतुल्य रकम प्रणाली से बाहर हो जाती है)। जब यह ओएमओ के जरिये बॉन्ड खरीदकर नकदी बढ़ाता है तो प्राप्तियां कम हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? विशुद्ध रूप से यह मांग-आपूर्ति का खेल होता है। जब बॉन्ड की मांग आरबीआई की तरफ से आती है तब कीमतें बढ़ती हैं और प्राप्तियां कम होती हैं। ओएमओ से बैंक को मदद मिलती है, क्योंकि इससे वे गैर-तरल प्रतिभूतियों के लिए कीमत का भुगतान कर इनसे छुटकारा पा लेते हैं और लाभ कमाते हैं।

इस बीच, बैंकों के पास सरकारी बॉन्ड की तादाद कम हुई है और इनमें कई के पास ओएमओ में भाग लेने के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियां नहीं हैं। 19.5 प्रतिशत नियामकीय शर्त के मुकाबले बैंक कुल देनदारी का 26 प्रतिशत बॉन्ड में रखते हैं, लेकिन तथाकथित लिक्विडिटी कवरेज अनुपात का पालन करने के लिए उन्हें अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है। इससे आरबीआई को बेचने के लिए उनके पास काफी कम रकम बच जाती है।

मौजूदा समय में उपलब्ध विकल्पों के मद्देनजर आरबीआई के नकदी प्रबंधन उपायों में यह नया हथियार एक स्थायी जरिया होगा। इसका इस्तेमाल कितनी बार होगा यह रुपये का स्तर तय करेगा। अक्टूबर 2018 के 74.48 के मुकाबले भारतीय रुपया इस समय कहीं मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर पर इसका मूल्यांकन अधिक है, जिससे यह उपाय करने की यह एक आदर्श स्थिति है। मेरी समझ में जब से शक्तिकांत दास ने आरबीआई की कमान संभाली है तब से यह उनका यह एक बेहतरीन कदम है।

(लेखक बिजनेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक हैं। वह जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ सलाहकार भी हैं।)

मुख्यमंत्री मोदी की चाल ने बता दिया था प्रधानमंत्री मोदी का हाल

नीति नियम

मिहिर शर्मा

सामान्य तौर पर देखें तो जब एक केंद्र सरकार अगले जनादेश के लिए चुनाव मैदान में उतर रही हो तो उसे आंकड़ों पर जांचना मुफीद रहेगा। मसलन उसे मिले अवसरों के अनुपात में वृद्धि के मोर्चे पर उसका प्रदर्शन कैसा रहा? इस मोर्चे पर विभिन्न पूर्ववर्ती सरकारों के समक्ष उसका प्रदर्शन कैसा है? घाटे के मोर्चे पर सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा और व्यय का कितना हिस्सा उत्पादक साबित हुआ?

दुर्भाग्यवश 2019 में यह विकल्प आसानी से उपलब्ध नहीं है। वजह यह कि इसके लिए जो आंकड़े इस्तेमाल किए जाने थे उन पर अब लोगों को यकीन ही नहीं है। जरा विचार कीजिए कि अगर पिछली सीरीज के आंकड़ों से मिलाकर देखें तो नोटबंदी के बाद के कुछ वर्षों के दौरान जीडीपी के आंकड़े पिछले वर्षों के प्रदर्शन के समान या बेहतर रहे हैं। आमतौर पर इस पर यकीन नहीं किया जाता क्योंकि अधिकांश संकेतक इस बात की गवाही नहीं देते कि हम वृद्धि के मोर्चे पर पिछली सरकारों से बेहतर हैं। कोई भी व्यक्ति जो सन 2000 की तेजी के दौर का गवाह रहा है वह इसे गलत बताएगा। गत सप्ताह देश के विभिन्न संस्थानों तथा विदेशों के 100 से अधिक अर्थशास्त्रियों ने एक शिकायती पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें देश की सांख्यिकी में राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कही गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी आंकड़ा जो सरकार की उपलब्धियों पर संदेह पैदा करता हो, उसे संशोधित किया जाता है या दबा दिया जाता है।

कुछ मामलों में मौजूदा सरकार के लिए यही मुफीद है कि उसके आंकड़ों का पिछली सरकारों से मिलान न किया जा सके। भारतीय इतिहास में कुछ ही सरकारों को ऐसे स्पष्ट लक्ष्य मिले हैं जैसे मौजूदा सरकार को। साफ है कि सरकार ने इन मौकों को गंवा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रदर्शन उम्मीद से कमतर रहा है। इस बात पर एक तरह की सहमति है। मोदी एक बड़े सुधारक साबित होंगे और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकेंगे, यह उम्मीद इसलिए गलत साबित हुई क्योंकि बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री उनके कदमों और प्रदर्शनों की गलत व्याख्या की गई।

सन 2013 में मैंने गुजरात मॉडल के प्रदर्शन पर नजर डाली थी और निष्कर्ष दिया था कि उसे बढ़ाचढ़ाकर पेश किया गया। उदाहरण के लिए 2004 से 2012 के बीच प्रति व्यक्ति खपत में बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से कम थी। मोदी के कार्यकाल में गुजरात में वृद्धि दर महाराष्ट्र या तमिलनाडु से कमजोर रही। बल्कि अधिकांश मानव विकास सूचकांकों पर प्रदेश अन्य राज्यों से पिछड़ गया था।

बतौर मुख्यमंत्री मोदी के प्रदर्शन को बढ़ाचढ़ाकर पेश किया गया और परिणामस्वरूप वह प्रधानमंत्री बन गए। अगर उसी तर्ज पर उन्हें दोबारा चुन लिया जाए तो चकित होने की आवश्यकता नहीं है।

नोटबंदी को छोड़ दें तो बतौर प्रधानमंत्री मोदी के कदमों में भी कुछ चौंकाने वाला नहीं है। सच तो यह है कि 2014 में जहां अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने उनको बाजार समर्थक सुधारक माना था, वहीं वह काफी हद तक यथास्थितिवादी नजर आए। वास्तव में उनसे यही अपेक्षा थी। मोदी ने भले ही 'न्यूनतम सरकार' का जुमला इस्तेमाल किया हो लेकिन वह प्रतीकात्मकता और जुमलेबाजी का एक शुरुआती उदाहरण भर है जिसके जरिये उन्होंने विभिन्न मतदाता वर्ग को प्रभावित किया।

मैंने उस वक्त मुख्यमंत्री रहे मोदी के भाषणों पर गौर किया और पाया उनके भीतर सुधारकों वाली बात नहीं है। आइए एक बार फिर याद करते हैं उन परिस्थितियों को। हममें से अधिकांश लोगों को याद होगा कि मुख्यमंत्री मोदी वर्षों तक वस्तु एवं सेवा कर की राह की सबसे बड़ी बाधा बने रहे जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद वह इसका श्रेय लूटते हैं। मुख्यमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियम शिथिल करने से केवल 'इटली के कारोबारियों' को फायदा होगा। उन्होंने कहा था कि श्रम कानूनों में बदलाव राज्यों को करना चाहिए केंद्र को नहीं। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पेट्रोल कीमतों को तार्किक बनाने का विरोध करते हुए कहा था कि यह खतरनाक है और इससे देश को नुकसान पहुंचेगा। प्रति परिवार गैस सिलिंडर की संख्या सीमित करने को उन्होंने जनता के साथ धोखा बताया था। स्वयं उनकी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जिस दिन संप्रग सरकार ने इन पिछड़े कदमों (डीजल को नियंत्रण मुक्त और एलपीजी सब्सिडी सीमित करने जैसे विवेकसम्मत निर्णय)की घोषणा की उसी दिन मोदी ने किसानों का 100 फीसदी कर्ज माफ किया और बिजली बिल में 50 फीसदी राहत दी। मोदी एक विकसित राज्य के सक्षम प्रशासक भर थे। वह प्रदेश की कुशल नौकरशाही और बड़े कारोबारियों से निजी रिश्तों पर निर्भर थे। कुछ लोगों ने कहा भी था कि यह कौशल प्रधानमंत्री कार्यालय में काम नहीं आता। वहां व्यक्तिगत परियोजनाओं के प्रबंधन के बजाय प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और क्षमता निर्माण जैसे अहम कार्य करने होते हैं।

निर्वाचन के पहले प्रधानमंत्री के वक्तव्य और उनका प्रदर्शन दोनों इस बात का सटीक ब्योरा देते हैं कि सरकार ने आगे चलकर कैसा प्रदर्शन किया। 2014 के पहले मुख्यमंत्री रहे मोदी ने कहा था कि बुनियादी ढांचा विकसित करना असली सुधार है। इस दिशा में वाकई काफी काम हुआ है। नीतिगत नवाचार और क्रियान्वयन के लिए सरकार काफी हद तक नौकरशाही पर निर्भर रही है। उसने निजीकरण से दूरी बनाए रखी और स्टार्ट अप को सहयोग के नाम पर सरकारी क्षेत्र की सहभागिता में इजाफा किया। सरकार ने निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण किया है। सरकार ने 25 वर्ष के उदारीकरण को पलटते हुए दोबारा शुल्क और औद्योगिक नीति रूपी क्षेत्रवार प्राथमिकता का दौर शुरू किया। गुजरात के तर्ज पर खपत में वृद्धि कमजोर बनी रही। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की खपत।

देश एक बार फिर आम चुनाव का सामना करने जा रहा है। ऐसे में कम से कम लोगों को यह पता होना चाहिए मोदी के संभावित दूसरे कार्यकाल से लोगों को किस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए। आर्थिक सुधार एजेंडे पर नहीं है। यह कभी एजेंडे पर था ही नहीं।

कानाफूसी

टिकट की चाह

आम चुनाव करीब आते ही टिकट वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। टिकट की चाह रखने वाले लोगों को इन दिनों राजनीतिक दलों के नेताओं से मेल-मुलाकात करते देखा जा सकता है। एक टीवी पत्रकार, जिनके पिता ने सन 2009 की लोकसभा में उत्तर प्रदेश की महाराजगंज सीट से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, वह इस बार अपने लिए कांग्रेस का टिकट चाहते हैं। उत्तराखंड में भाजपा नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी के कांग्रेस में शामिल होने के साथ-साथ देश के तमाम हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें नेता और उनके परिजन तेजी से दल बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद टिकट चाहने वालो में अफरातफरी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी में कई मौजूदा सांसद टिकट कटने की आशंका से दो-चार हैं। इनमें से कई तो कांग्रेस से भी चर्चा कर रहे हैं।

किशोर और कुमार

ऐसा प्रतीत होता है कि जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपनी ही पार्टी में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के पुराने नेता इस बात को लेकर नाराज हैं कि वह पार्टी में नए हैं और उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव भी नहीं है। इसके बावजूद उन्हें बिहार में टिकट वितरण का काम सौंपा गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि किशोर के हर छोटे बड़े कदम की पार्टी नेता अपनी बैठकों में आलोचना करते हैं। कई नेता जो प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, उन्हें नीतीश से किशोर की शिकायत करते हुए भी देखा गया है।

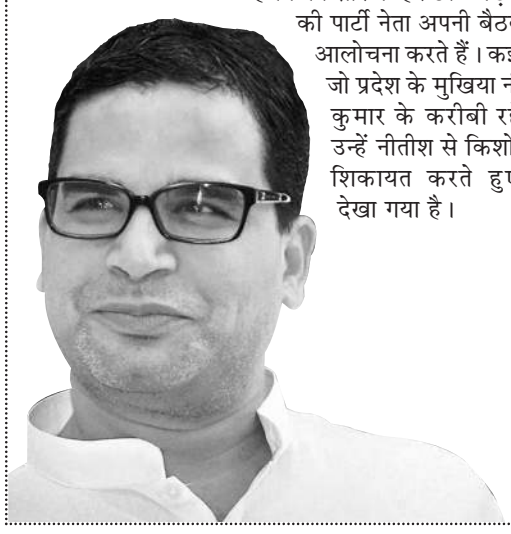

आपका पक्ष

ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन

इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देने के लिए इसे पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त करने की जरूरत है। इसके अलावा देश में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की जरूरत है। वर्तमान में शहरों का ढांचा तथा आपूर्ति इसके लिए तैयार नहीं है। अत: जगह-जगह पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य शीघ्रता से हो। चार्जिंग स्टेशनों का आवंटन या वितरण कुशल हाथों में हो। इन्हीं को बजट प्रावधान करने के लिए आवश्यक संसाधन भी मुहैया कराए जाएं। ग्राहकों में जागृति का प्रश्न भी सुलझाया जाए। अगर उन्हें भरोसा नहीं होगा तो ऐसे वाहन बिक्री में पिछड़ जाएंगे। ई-ऑटो के लिए सरकारी नीति का अनुकूल होना भी बहुत जरूरी है जो राज्य सरकार निर्धारित करती है। केंद्र का इसमें सहयोग होता तो ई-वाहन निर्माण, वितरण एवं व्यवहार शीघ्रता से होगा।

हिम्मत जोशी, नागपुर

देश में ई-वाहनों के अधिक प्रचलन के लिए बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना जरूरी है

जनधन खाते में बढ़े सुविधाएं

बैंकों में एक हजार रुपये से साधारण बचत खाता खुल जाता है। इस खाते में असीमित रुपये जमा करने के साथ ही उचित दर पर ब्याज मिलता है। वहीं शून्य राशि में खुलने वाले जनधन खाते में सीमित रकम ही जमा कर सकते हैं। इस पर ब्याज भी साधारण खाते से कम मिलता है। जनधन खाते में एक हजार रुपये जमा करने के बाद भी यह साधारण खाते में नहीं बदल सकता है। जनधन खाते में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। शून्य राशि के बदले लोग एक हजार रुपये तो इस खाते में जमा कर ही सकते हैं।

राकेश जैन, सतना

चुनावी जुमले का नहीं रहा वक्त

केंद्र में मोदी सरकार बनने से पहले भाजपा ने मतदाताओं से बड़े-बड़े वादे किए थे। हर साल लाखों नौकरियां देने और विदेश से काला धन लाकर लोगों के खाते में 15 लाख रुपये डालने जैसी घोषणाओं को जनता भूली नहीं है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तारीख की घोषणा से पहले मोदी सरकार शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रमों में व्यस्त दिखी। अगर कोई पार्टी अपने घोषणापत्र में कोई लुभावनी घोषणा करती है तो सत्ता में आने के बाद उसे पूरा करने में विफल रहने वाले दल पर जुर्माने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इससे उस पार्टी को सबक मिलेगा और जनता में लोकतंत्र को लेकर विश्वास बढ़ेगा।

नीलम शर्मा, इंदौर

सरकार की घोषणाएं नहीं हैं अनुचित

केंद्र सरकार ने चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही अपने शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रमों को पूरा किया जिसके चलते उसमें चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं है। जहां तक मतदाताओं को लुभाने के लिए इन घोषणाओं के उचित या अनुचित होने का प्रश्न है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही यह सिलसिला जारी है। इनमें से जनधन खाता और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। तो कुछ योजनाओं के इच्छित परिणाम सामने नहीं आए। जीएसटी से पैदा हुई समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।